

मिशन हास्पिटल कैंपस खाली करने हाईकोर्ट ने दी 30 दिन की मोहलत

48 घंटे में बेदखली का था नोटिस, 17 ने लगाई थी याचिका

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

मिशन हास्पिटल कैंपस में रहने वाले 17 परिवारों को तहसीलदार ने 23 जुलाई को नोटिस जारी कर 48 घंटे के भीतर जमीन खाली करने को कहा था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल बेंच ने मानवीय आधार पर राहत देते हुए 30 दिनों की मोहलत दी है। इसके बाद परिसर नहीं खाली करने पर कार्रवाई की छूट दी गई है।

मिशन हास्पिटल कैंपस निवासी शांति दानी, अमिता मसीह, शाहिद हुसैन, विनीत मसीह, शांता ब्राउन, अरशद हुसैन समेत अन्य को तहसीलदार नजूल ने 23 जुलाई को

हाईकोर्ट ने मिशन हास्पिटल प्रबंधन की लीज रिन्यूअल याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की सिंगल बेंच ने जिला प्रशासन की कार्रवाई को सही और वैधानिक ठहराया।

नोटिस जारी कर 48 घंटे में जमीन खाली करने को कहा था, इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। कहा कि वे लंबे समय से रह रहे हैं। नियमित रूप से बिजली बिल, टैक्स आदि का भुगतान कर रहे हैं। उनका कहना था कि तहसीलदार ने बिना सुनवाई और छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत अधिकार से बाहर जाकर जल्दबाजी में कार्रवाई की गई है। हाई कोर्ट ने याचिका

खारिज कर दी, लेकिन मानवीय आधार पर याचिकाकर्ताओं को 30 दिन का समय देते हुए कहा कि वे इस अवधि के भीतर परिसर खाली करें। याचिकाकर्ताओं के पास एसडीएम के समक्ष अपील का विकल्प उपलब्ध है। इसलिए इस स्तर पर हाई कोर्ट का हस्तक्षेप उचित नहीं। लेकिन, बरसात के मौसम को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को 30 दिन की मोहलत दी।